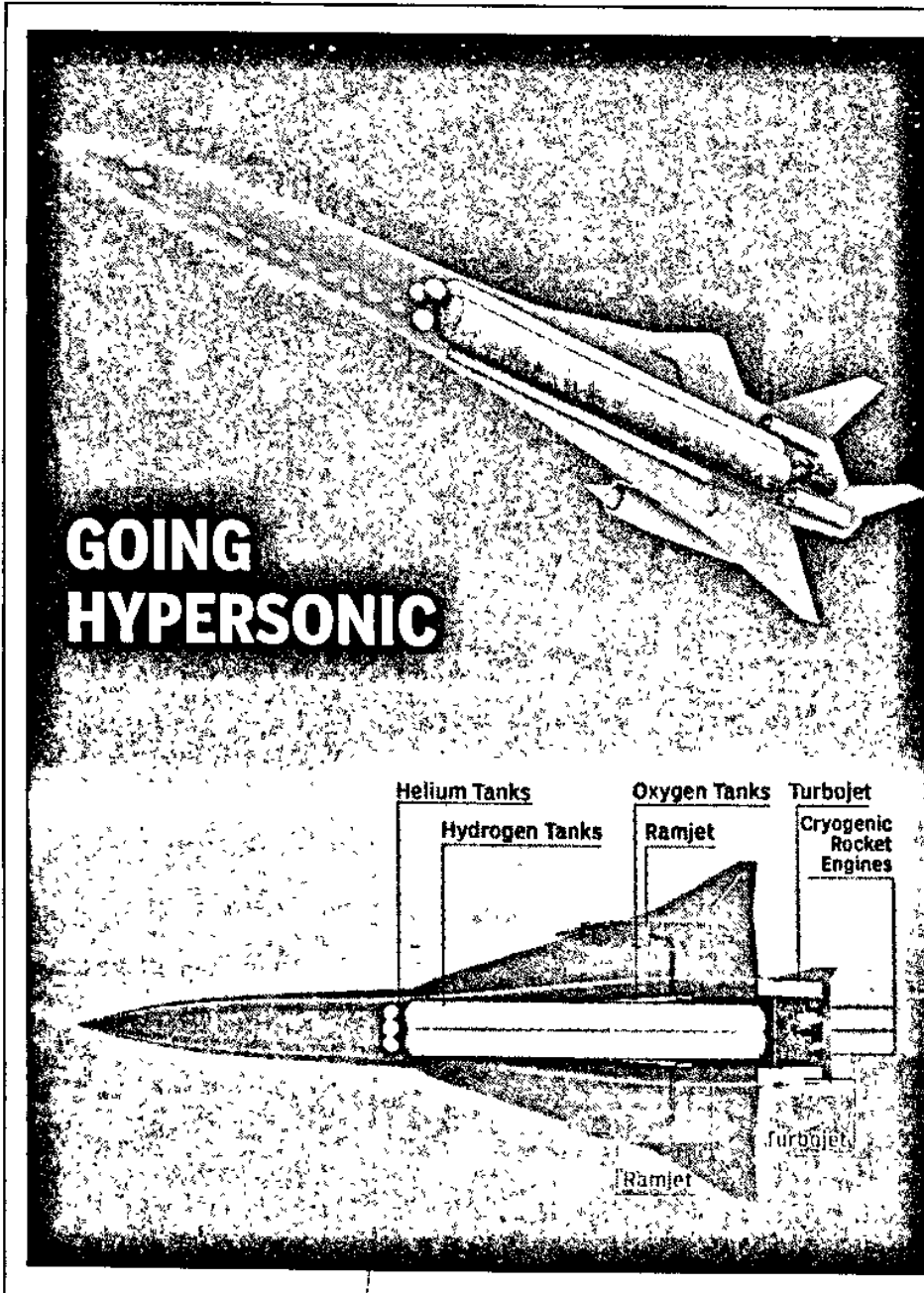


# Newspaper Clips

June 20, 2011

Times of India ND 20/06/2011 P-15



**GOING  
HYPERSONIC**

## Green rocket plane to zip from Paris to Tokyo in 2.5hrs

Paris: European aerospace giant EADS on Sunday unveiled its "Zero Emission Hypersonic Transportation" (Zehst) rocket plane it hopes will be able to fly from Paris to Tokyo in 2.5 hours by around 2050.

The low-pollution plane to carry between 50 and 100 passengers will take off using normal engines powered by biofuel made from seaweed before switching on its rocket engines. The rocket engines, powered by hydrogen and oxygen whose only exhaust is water vapour, propel the plane to a cruising altitude of 32km, compared to today's passenger jets which fly at around 10,000 metres.

To land, the pilot cuts the engines and glides down to Earth before reigniting the regular engines before landing.

EADS hopes to have a prototype built by 2020 and for the plane to eventually enter service around 2050. The project is being developed in collaboration with Japan. AFP

# आईआईटी को और ज्यादा स्वायत्तता की जरूरत नहीं

स्वाति गर्ग

देश के सभी प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान खुद को बिना सरकारी सहायता के चलाना टेढ़ी खीर मानते हैं। ऐसे में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को स्वायत्त करने की मांग करने वाली काकोडकर समिति की रिपोर्ट पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) और आईआईटी परिषद ने फिर से विचार करना तय किया है।

नतीजे के रूप में सभी आईआईटी ने खुद के लिए अतिरिक्त स्वायत्तता की आवश्यकता को पूरी तरह से नकार दिया। आईआईटी निदेशकों और प्रोफेसरों ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में स्वीकार किया कि स्वायत्तता की जरूरत नहीं है। सभी का कहना है कि अच्छे से काम करने के लिए आईआईटी को पर्याप्त स्वायत्तता मिली है।

आईआईटी मद्रास के निदेशक एम एस अनंत का स्वायत्तता को

लेकर कहना है कि मेरे हिसाब से आईआईटी संस्थानों के पास वर्तमान में पर्याप्त स्वायत्तता है। संस्थान के रूप में इन्हें और स्वायत्त नहीं करना चाहिए। मैं स्वायत्तता बढ़ाने के मामले में जरूरत पड़ने पर लड़ने को भी तैयार हूँ।

परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व चेयरमैन अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में बने इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट में स्वायत्तता की वकालत की है। रिपोर्ट की मानें तो वित्तीय प्रबंधन और परिचालन से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को आईआईटी परिषद और एमएचआरडी से लेकर आईआईटी बोर्ड को दे दिया जाना चाहिए। इससे आईआईटी संबंधी वित्तीय सहयोग में सरकारी भागीदारी को कम करके आईआईटी को स्वायत्त बनाया जा सकेगा। साथ ही विकास संबंधी कार्यों में भी वित्तीय बाधा दूर हो जाएगी।

आईआईटी खडगपुर के प्रोफेसर ने स्वायत्तता के मसले पर बताया कि काकोडकर का पूरा सुझाव



देश के ज्यादातर आईआईटी संस्थान के निदेशकों और प्रोफेसरों का मानना है कि अच्छे से काम करने के लिए आईआईटी को पर्याप्त स्वायत्तता मिली है। अब और ज्यादा स्वायत्तता की दरकार नहीं है। कुछ का यह भी मानना है कि आईआईटी की जगह आईआईटी परिषद को सभी वित्तीय निर्णय लेने के लिए और मजबूत बनाया जाना चाहिए।

केवल आईआईटी को स्वायत्तता प्रदान किये जाने पर ही आधारित है। मैं इस स्वायत्तता के बाद होने वाले विकास को लेकर सहमत नहीं हूँ। हमें सुनहरे भविष्य के लिए लंबी दौड़ की जरूरत है।

सभी आईआईटी का अपना बोर्ड है। आईआईटी परिषद इन बोर्डों का

शासी निकाय है जोकि एमएचआरडी, केंद्रीय शिक्षा सचिवों और सभी आईआईटी निदेशकों से लगातार जुड़ा रहता है। आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक गौतम बरुआ आईआईटी की जगह आईआईटी परिषद को स्वायत्तता देने को सही बताते हैं। बरुआ का कहना है कि

वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई रोक को हटाकर आईआईटी परिषद को सभी वित्तीय निर्णय लेने के लिए और मजबूत बनाया जाना चाहिए। साथ ही पदों की संख्या, वेतन मान, पदोन्नति संबंधी नियम, भर्ती नियम और खरीद संबंधी नियमों से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार भी परिषद को ही होना चाहिए। बरुआ ने कहा कि बोर्ड पूरी तरह से सरकार, संकाय सदस्यों और स्टाफ का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

काकोडकर समिति ने स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के लिए फीस को 50,000 से 5 गुना बढ़ाकर 2,50,000 रुपये किये जाने की सिफारिश भी की है। समिति का मानना है कि बड़ी फीस से मिलने वाली अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल आईआईटी को पूरी तरह से स्वायत्तता के लिए किया जाएगा।

जनवरी 2011 में समिति ने रिपोर्ट की पहली प्रति मानव संसाधन मंत्रालय को भेजी थी।

फीस बढ़ोत्तरी और अन्य समस्याओं से जुड़ी नई सिफारिशों में योग्य उम्मीदवारों के लिए छात्रवृत्ति की बात कही गयी है। रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 साल में एक बार अंतरराष्ट्रीय स्तर के समूह द्वारा आईआईटी की समीक्षा होगी। काकोडकर कमेटी का गठन अक्टूबर 2009 में किया गया था। काकोडकर के अलावा इसमें इन्फोसिस के पूर्व मानव संसाधन निदेशक टी. वी. मोहनदास पई, जुबिलेंट ऑर्गेनाइसिस के सह अध्यक्ष और चेयरमैन हरि भरतिया, केरल विश्वविद्यालय (स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान) के कुलपति के. मोहनदास और आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला शामिल थे। इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक गौतम बरुआ, आईआईटी मंडी के निदेशक टी. गौसाल्वेस और आईआईटी कानपुर के चेयरमैन एम. आनन्दकृष्णन पैनल में विशेष रूप से आमंत्रित थे।

मैं इस स्वायत्तता के बाद होने वाले विकास को लेकर सहमत नहीं हूँ। हमें सुनहरे भविष्य के लिए लंबी दौड़ की जरूरत है।

Publication: The Times Of India Delhi; Date: Jun 20, 2011; Section: Education Times; Page: 52;

## Education woes

THE federation of Indian commerce and industry (FICCI) has written a letter to Oscar Fernandes, chairman, parliamentary standing committee on HRD on the recent case of 100% as cut-off marks for undergraduate admissions for the commerce stream in Shri Ram College of Commerce (SRCC), Delhi. The letter states that the 100% cut-off is an indication of the desperate situation of children and parents today due to the dearth of quality higher education institutions. Dismal show of quality higher education is further substantiated by the recent QS rating of universities across Asia, in which only IIT Mumbai features in the top 200, it stated.

FICCI urged the government to take up higher education reforms on priority. It stressed that the impending national commission for higher education and research (NCHER) bill, 2010, should be tabled in the parliament. It also stated that foreign education providers cannot provide a degree in India, deters them from starting operations in India. It asked the government to encourage a culture of transparency and self regulation amongst higher education providers and to expeditiously pass the prohibition of unfair practices in technical educational institutions, medical educational institutions and universities bill, 2010.